बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 170 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 21 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने नरेश बालियान के केस से खुद को किया अलग, नहीं बताया कारण

नई दिल्ली। मकोका मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को अलग कर लिया। बालियान ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम- 1999 के तहत एक संगठित अपराध से संबंधित मामले में जमानत मांगी थी। अब यह मामला 23 अप्रैल को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध होगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले से खुद को अलग करने का कोई कारण नहीं बताया।

दिल्ली हाई कोर्ट का अभूतपूर्व कदम, Order Reserve होने के बाद भी केजरीवाल को जवाब की इजाजत

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के उस दावे के संबंध में अपनी लिखित दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी, जिसमें जांच एजेंसी से जुड़े कथित शराब नीति घोटाले के मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को अलग करने की बात कही गई थी। जस्टिस शर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक अपवाद बना रही हैं, ताकि कल उन्हें यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई।

जस्टिस शर्मा को सोमवार दोपहर 2.30 बजे (जैसा कि सुबह पहले सूचित किया गया था) इस बात पर फैसला सुनाना था कि क्या कोर्ट सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करेगा या नहीं, जिसमें फरवरी में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आबकारी मामले में 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि, केजरीवाल द्वारा नई दलीलें पेश किए जाने के बाद, कोर्ट ने अब फैसला सुनाने का समय शाम 4.30 बजे तक के लिए टाल दिया है। रिक्यूज़ल (मामले से खुद को अलग करने) के खास पहलू पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रखने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल के जवाब को लिखित दलीलों के तौर पर रिकॉर्ड पर ले रहा है–ऐसा वह अपनी तरफ से खास कोशिश करके कर रहा है–ताकि कल को केजरीवाल को यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई; हालांकि, पिछली सुनवाई की तारीख पर इस कोर्ट ने यह पूरी तरह साफ़ कर दिया था कि अब इस मामले पर आगे कोई बहस नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल

तुषार मेहता ने केजरीवाल की नई अर्जी को रिकॉर्ड पर लिए जाने का विरोध करते हुए अदालत से कहा, मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ पूरे देश में, किसी भी अदालत के सामने – चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी जगह जैसे ही किसी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, उसके बाद कोई भी नई दलील या दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर जगह एक समान रूप से किया जाता है... शायद किसी भी दूसरे आम आदमी (सामान्य नागरिक) को यह सुविधा नहीं मिली होती... देश की किसी भी अदालत में, एक बार फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के बाद, जवाबी हलफनामा दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह तो हद से कुछ ज्यादा ही हो रहा है...

उनका हलफनामा किसी वकील ने तैयार किया है, यह बात साफ-साफ ज़ाहिर है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की नई अर्जी को रिकॉर्ड पर लिए जाने का विरोध करते हुए अदालत से कहा, मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ पूरे देश में, किसी भी अदालत के सामने – चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी जगह – जैसे ही किसी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, उसके बाद कोई भी नई दलील या दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर जगह एक समान रूप से किया जाता है... शायद किसी भी दूसरे आम आदमी (सामान्य नागरिक) को यह सुविधा नहीं मिली होती... देश की किसी भी अदालत में, एक बार फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के बाद, जवाबी हलफनामा दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह तो हद से कुछ ज्यादा ही हो रहा है... उनका हलफनामा किसी वकील ने तैयार किया है, यह बात साफ-साफ ज़ाहिर है। अदालत ने केजरीवाल को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि उन्हें हितों के टकराव के आधार पर पक्षपात की आशंका है, क्योंकि जस्टिस शर्मा के दो बच्चे सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। सीबीआई ने उसी दिन अपनी लिखित दलीलें पेश की थीं, जिसमें उसने केजरीवाल की दलीलों का खंडन किया था।

दिल्ली की सड़कों पर नजर नहीं आएंगी पेट्रोल बाइक्स! रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में वाहन नीति को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, जो आने वाले वर्षों में सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है. अगर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू होती है, तो 2028 के बाद रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से यादा हो सकती है. सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, हालांकि कुछ फैसलों पर असहमति भी सामने आ रही है.

2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का रजिस्ट्रेशन, बड़ा बदलाव तय

नई नीति के मसौदे के अनुसार जनवरी 2028 से राजधानी में नई पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद किया जा सकता है. इसका सीधा असर यह होगा कि हर साल रजिस्टर होने वाली नई गाड़ियों में 60 से 65 प्रतिशत तक हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की हो जाएगी. फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव जुटा रही है, लेकिन पेट्रोल बाइक पर रोक को लेकर कई लोग अपनी चिंता जता रहे हैं.

वाहनों से बढ़ता प्रदूषण बना नीति का आधार

सरकार का मानना है कि दिल्ली के कुल प्रदूषण में 25 से 30 प्रतिशत योगदान वाहनों का है. इसमें भी टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी 15 से 18 प्रतिशत तक आंकी गई है. यही वजह है कि नीति में सबसे बड़ा फोकस बाइक और स्कूटर जैसे वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने पर रखा गया है. हालांकि, 2028 से पहले खरीदी गई पेट्रोल बाइक सड़कों पर चलती रहेंगी.

दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का भारी दबाव

राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तक दिल्ली में कुल 87 लाख से यादा वाहन पंजीकृत हैं. इनमें करीब 59 लाख टू-व्हीलर्स शामिल हैं. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अभी करीब 4.7 लाख के आसपास है, जो कुल वाहनों की तुलना में काफी कम है. बीते दो साल में 10 लाख से यादा नए टू-व्हीलर रजिस्टर हुए, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी महज 6.75 प्रतिशत रही.

इलेक्ट्रिक वाहनों से खर्च में कमी और पर्यावरण को राहत

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स अपनाने से आम लोगों को दोहरा फायदा होगा. एक ओर जहां ईंधन खर्च में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी. सरकार इसी सोच के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है.

दिल्ली में फिलहाल करीब 4.71 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जिनमें ई-रिक्शा, ई-ऑटो, कार, बस और बाइक शामिल हैं. सरकार ने नई ईवी नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 10 मई तक आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं. इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो, ई-बाइक और स्कूल बसों को भी इलेक्ट्रिक करने की योजना शामिल की गई है इस प्रस्तावित बदलाव के साथ दिल्ली न सिर्फ प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण पेश करने की तैयारी में है.

दिल्ली के पहले डबल-डेकर फ्लाईओवर की अड़चन खत्म, अक्टूबर से मेट्रो के नीचे दौड़ेंगी गाड़ियां; सबवे होगा बंद

पूर्वी दिल्ली।

वजीराबाद रोड पर बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इन दिनों बंद है। फ्लाईओवर के उतरने और चढ़ने के लिए जहां रैंप बनना है, वहां करीब 80 पेड़ आ रहे हैं, जो निर्माण में बाधा बने हुए हैं।

भजनपुरा का अंडरग्राउंड सबवे होगा बंद

अब इन पेड़ों को हटाने की अनुमति मिल गई है। पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। भजनपुरा में बने वर्षों पुराने भूमिगत सबवे को पीडब्ल्यूडी जल्द ही बंद करने जा रहा है।

यह सबवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बीच में आ रहा है। सड़क पार करने वाले राहगीरों के लिए भजनपुरा मेट्रो स्टेशन सेतु का काम करेगा।

ऊपर मेट्रो और नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी

1.4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण डीएमआरसी व पीडब्ल्यूडी मिलकर कर रहे हैं। यह दिल्ली का पहला ऐसा फ्लाईओवर है, जिसके ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे वाहन दौड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी को काफी मशक्कत के बाद पेड़ों को हटाने की अनुमति मिली है। धीरे-धीरे पेड़ों को हटाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर से उतरने और चढ़ने के लिए रैंप बनाना है। पेड़ों की वजह से रैंप नहीं बन पा रहे हैं। अगले दो माह में डीएमआरसी रैंप के लिए टेंडर जारी करेगा। उम्मीद जताई कि अक्टूबर में यह फ्लाईओवर वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा।

फ्लाईओवर शुरू होते ही जाम मुक्त हो जाएगा वजीराबाद रोड

घोंडा के विधायक अजय महावर ने कहा कि यह ऐसा फ्लाईओवर है, जहां एक ही पिलर पर दो स्तर होंगे। मेट्रो का हिस्सा बनाकर शुरू कर दिया गया है। जिस पर वाहन चलने है, उस हिस्से के रैंप बनने रह गए हैं। 200 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है। दावा किया कि फ्लाईओवर शुरू होने से यमुना विहार, भजनपुरा, चांदबाग, गोकलपुरी का जाम खत्म हो जाएगा। लाखों लोग जाम में फंसे बिना इसका आनंद लेंगे।

आपको सरकार में ढोने के लिए रखा है क्या, अधिकारियों पर भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता; सुस्ती पर लगाई फटकार

बाहरी दिल्ली।बाहरी दिल्ली में विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सख्त रुख देखने को मिला। सोमवार को आजादपुर मंडी, गुप्ता मार्केट और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गुप्ता मार्केट के पास लंबे समय से रास्ते से अवरोधक/पत्थर न हटने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, यहां तक कहा- आपको सरकार में किस लिए रखा है, ढोने के लिए। मुख्यमंत्री ने आजादपुर इलाके में डीएमआरसी और पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आजादपुर के गुप्ता मार्केट के सामने काम की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति और लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा, जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के वकील ने की आत्महत्या, होटल की 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान

नई दिल्ली ।

राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित कनॉट प्लेस इलाके में स्थित द रॉयल प्लाजा होटल में एक युवा वकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 19 अप्रैल की रात करीब 9:15 बजे की पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक की पहचान 26 वर्षीय राजेश सिंह के रूप में हुई है, जो महावीर एन्क्लेव, दिल्ली का निवासी था और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता था। पुलिस के मुताबिक, राजेश सिंह 18 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे होटल में ठहरा था।

जांच के दौरान सामने आया कि उसने कथित तौर पर होटल की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना के हर पहलू की जांच की जा सके। परिवार के बयान के अनुसार, इस मामले में किसी तरह की साजिश या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका नहीं जताई गई है। फिलहाल पुलिस संबंधित धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

दिल्ली बनेगी चिप कैपिटल- सेमीकंडक्टर पॉलिसी से खुलेंगे रोजगार के दरवाजे, युवाओं के लिए सुनहरा सिग्नल

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका मकसद दिल्ली को चिप डिजाइन, रिसर्च, पैकेजिंग और हाईटेक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाना है। इससे तकनीक के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर मिलेंगे जिससे युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नीति सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम मानी जा रही है। क्योंकि इससे रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान, नवाचार और असेंबल गतिविधियों का मजबूत केंद्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम कड़ी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, मेडिकल उपकरण, रक्षा तकनीक और डिजिटल सिस्टम से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें इसी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप होगी और देश में सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका होगी।

पांच बड़े क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

सरकार के मुताबिक, प्रस्तावित नीति में पांच प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इनमें पहला क्षेत्र सेमीकंडक्टर डिजाइन और बौद्धिक संपदा विकास है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना, तीसरा, विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियां जैसे असेंबल, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यानी एटीएमपी तथा ओएसएटी इकाइयों का विकास, चौथा, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट तैयार करना और पांचवां, स्टार्टअप और औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाना होगा।

दिल्ली में नौकरियों के अवसर

इस नीति का सबसे बड़ा फायदा रोजगार के क्षेत्र में होगा। सरकार का मानना है कि चिप डिजाइन, रिसर्च, एडवांस पैकेजिंग, टेस्टिंग और टेक सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नई नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा, मशीन डिजाइन और प्रबंधन से जुड़े युवाओं को खास फायदा मिल सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप और उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी के जरिए छात्रों को सीधे उद्योग से जोड़ा जाएगा।

निवेशकों के लिए बनेगा बेहतर माहौल

सरकारी नीति के तहत निजी निवेश बढ़ाने पर जोर है। इसके लिए पूंजीगत सब्सिडी, आधारभूत ढांचे का विकास, परिचालन लागत कम करने और कारोबार आसान बनाने जैसे कदम प्रस्तावित हैं। घरेलू और विदेशी कंपनियों को दिल्ली में निवेश के लिए आकर्षित करने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि यदि डिजाइन, पैकेजिंग और टेस्टिंग सेक्टर में बड़े निवेश आते हैं तो उससे सहायक उद्योग भी तेजी से बढ़ेंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नया बाजार मिलेगा।

सेमीकंडक्टर आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मोबाइल से लेकर रक्षा उपकरण तक हर आधुनिक तकनीक में इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली इस क्षेत्र में मजबूत नीति लाती है तो इसका असर देशभर में दिख सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि नीति लागू होने के बाद दिल्ली में मजबूत, नवाचार आधारित और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा।

होर्मुज बना हथियार

49 दिनों बाद ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट खोलने के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही इसे फिर से बंद किए जाने की खबर से दुनियाभर में फिर हताशा फैल गई। 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमला करते ही होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही बाधित हो गई थी। कुछ दिन बाद ईरान ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया था जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ौतरी हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस समुद्री मार्ग को फिर से बंद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर मानसिकता एक बार फिर सामने आ गई जब उन्होंने धमकी दी कि ईरान ने भले ही होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है लेकिन अमेरिका तब तक होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेगा जब तक ईरान से उनकी डील नहीं हो जाती। ट्रम्प की इस धमकी के बाद ईरान ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया और अमेरिका से आगे की बातचीत करने से साफ इंकार कर दिया। ट्रम्प ने नाकेबंदी इसलिए लगाई थी जिसका उद्देश्य तेहरान पर दबाव बनाकर होर्मुज को खुलवाना और पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को स्वीकार कराना था। ईरान द्वारा इस समुद्री रूट को खोलने की घोषणा के बावजूद ट्रम्प की धमकियां ईरान पर दबाव बनाए जाने की रणनीति का ही हिस्सा है। अस्थिर युद्ध विराम के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे अभी भी सामने हैं जैसे ईरान के संवर्धित यूरेनियम क्या अमेरिका हासिल कर लेगा? क्या ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम धीमा करेगा? दिनभर ऐसी रिपोर्टें भी खबरिया चैनलों पर आती रहीं कि अमेरिका अरबों डॉलर देकर उसका यूरेनियम डस्ट खरीद लेगा लेकिन ईरान की शक्तिशाली आईआरजीसी ने अमेरिकी दावों को नकार दिया। होर्मुज पर तनातनी के बाद युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित हो गया। ईरान ने युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट को एक सुपर हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है। छोटी पनडुब्बियों और बारूदी सुरंगों के जरिये इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कर ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर आर्थिक दबाव बनाने का जरिया बना लिया है।

ईरान ने इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने के आरोप झेलते हुए इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया। ईरान जानता है कि इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित कर किसी भी पारम्परिक सैन्य ताकत के मुकाबले कहीं यादा रणनीतिक फायदे वाला है। पूरी दुनिया उस भयावह स्थिति में वापिस नहीं लौटना चाहेगी जब ट्रम्प ने एक सभ्यता को समाप्त करने की धमकी दी थी और ईरान ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए मानव ढालों का इस्तेमाल किया था। वह क्षण दहशत का चरम था जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत का दावा करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी पक्ष लड़ाई जारी रखने का जोखिम नहीं उठाना चाह रहा। यह भी सचाई है कि ट्रम्प युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाश कर रहे थे और ईरान भी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। युद्ध विराम के बावजूद एक बुनियादी दिक्कत बनी हुई थी, वह थी हिजबुल्लाह। लेबनान में जंग इजराइल और लेबनानी सेना के बीच नहीं, बल्कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच है। हिजबुल्लाह वार्ता का हिस्सा नहीं रहा है। हिजबुल्लाह के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर इजराइली हमले बंद हो जाते हैं तो उनकी सेना इजराइल पर हमले करना बंद कर देगी। यह शिया उग्रवादी समूह कमजोर तो हो गया है, लेकिन अभी तक पराजित नहीं हुआ है। इजराइल ने यह भी कहा है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपने कब्जे वाले इलाके से सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, जबकि हिजबुल्लाह 2 मार्च से पहले की स्थिति में लौटने पर जोर दे रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान के साथ शांति समझौते का एक 'ऐतिहासिक मौका' है, लेकिन ऐसे किसी भी समझौते में लेबनानी सेना से कहीं यादा मजबूत और एक व्यापक राजनीतिक एवं सामाजिक नेटवर्क बनाए रखने वाले हिजबुल्लाह को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि अब युद्धविराम लागू हो चुका है, लेकिन शांति अभी भी दूर की कौड़ी ही है।होर्मुज स्ट्रेट?खुलने की खबर से भारत समेत पूरी ?दुनिया को राहत मिली थी। कचे तेल की कीमतें 12 फीसदी टूटकर 83 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई थी। सप्लाई चेन की बाधाएं खत्म होने की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजार गुलजार हो गए?थे। युद्ध टलने की खबर से निवेशकों का रुझान सोना-चांदी में फिर से देखा गया था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेल और गैस की सप्लाई सामान्य होने से महंगाई का खतरा टल जाएगा लेकिन गुड न्यूज बैड न्यूज में बदल गई। अब तेल और ऊर्जा संकट गहराया जाना तय है। अगर यही हाल रहा तो कीमतें बढ़ना तय हैं। भारत क्योंकि अपनी जरूरत का यादा तेल खाड़ी देशों से मंगाता है इसलिए उसका तेल आयात बिल रोजाना बढ़ रहा है। ईरान के पास परमाणु बम भले ही न हो लेकिन उसने होर्मुज को अपना ताकतवर हथियार बना लिया है। देखना होगा इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है।

सम्पादकीय...

मैदान-ए-जंग बनती ज रही बंगाल की सियासी ज़मीन

हमने रंगमंच पर मंझे हुए अभिनेताओं को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बराबर देखा है पर देश के सियासी अभिनेताओं को हम सिर्फ चुनाव में ही अपनी कला का प्रदर्शन करते देखते हैं जिस तरह आज बंगाल में दिख रहा है। इस चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी दी है। बंगाल के इस चुनावी समर में चुनावी मंच पूरी तरह से रंगमंच में परिवर्तित हो चुका है और बंगाल की ज़मीन भी मैदान-ए-जंग में बदल चुकी है। अभी अभी असम के विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ है और बंगाल में चुनावी प्रचार अंतिम समय मे चल रहा है ऐसे में सियासी पारा चरम पर पहुंचना लाज़िमी है। नेता के बिगड़ते बोल ने इस चुनाव को और अलग रंग दे दिया है। भाजपा के शुभेन्दु अधिकारी कभी कभी जोश में आकर अपने गुस्से का इज़हार कर बैठते है तो टीएमसी की ममता बनर्जी जिन्हें दीदी के नाम से सम्बोधित किया जाता है भी अपने लव लश्कर के साथ सड़कों पर उतर कर समर्थन की अपील करती दिख रही हैं। भाजपा एक तरफ़ इस चुनाव को किसी भी क़ीमत पर जीतना चाहती है और इसलिए वह चुनाव को हिन्दू मुस्लिम करने से नहीं चूक रही। यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्य नाथ की भाषा लोगों के सर चढ़ कर खूब बोल रही है तो तृणमूल कांग्रेस की सयानी घोष शानदार गायकी के ज़रिए अपना धर्मनिरपेक्षता का चुनावी तीर निशाने पर लगाने से नहीं चूक रहीं। चुनावी मंच से पार्टी के प्रतिनिधि,प्रत्याशी व स्टार प्रचारक अपनी पार्टी की नीति व घोषणा पत्र के हिसाब से भाषण देते हुए लोक लुभावने वादे भी करते नज़र आ रहे हैं। हमने रंगमंच पर मंझे हुए अभिनेताओं को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बराबर देखा है पर देश के सियासी अभिनेताओं को हम सिर्फ चुनाव में ही अपनी कला का प्रदर्शन करते देखते हैं जिस तरह आज बंगाल में दिख रहा है। इस चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी दी है लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के मध्य है। बंगाल के इस चुनावी समर में चुनावी मंच पूरी तरह से रंगमंच में परिवर्तित हो चुका है और बंगाल की ज़मीन मैदान-ए-जंग में बदल चुकी है। एक जमाने में चुनाव के दौरान हमारे प्रत्याशी चुनावी मंच से रोटी, कपड़ा मकान के अलावा रोजगार किसान मज़दूर मंहगाई सड़क पानी, बिजली व शिक्षा की बात करते थे। अब आज की सियासत पहले वाली सियासत नहीं रही जब कोई चुनावी प्रत्याशी अपने विरोधी प्रत्याशी के साथ बैठ कर चाय पीता हो।यहाँ तो आज अनुशासन को ठेंगा दिखाते हुए ये नेता एक दूसरे को झूठा साबित करने पर आमादा हैं।किसी को रोजगार मिले न मिले पर पर ये नेता इन बेरोजगारों को भी जाति व धर्म का पाठ पढ़ाने से बाज़ नहीं आ रहे हैं।देश के माननीय प्रधानमंत्री तक को मंच से बाहरी करार दिया जा रहा जबकि वे भी भारत के अभिन्न अंग गुजरात प्रान्त से हैं।वहीं हमारे उच पदासीन राजनीतिक व्यक्ति एक जनता द्वारा चुनी मुख्यमंत्री को गुंडा कहने से नहीं हिचकते।अब सवाल यह कि हमें ज़रूरत है राशन ,रोजगार ,शिक्षा,स्वास्थ्य की तो ये चुनावी रंगमंच के सियासी अभिनेता हमें धर्म व जाति में बांट कर अपना उल्लू सीधा करना सीधा करना चाहते हैं।

ईरान के अंदर क्या चल रहा है - बाहर जंग, अंदर खींचतान, भीतर से उठते सवाल क्या बताते हैं

जाहिद खान

असल मसला यहीं से शुरू होता है। एक तरफ ऐसा संदेश गया कि होर्मुज का रास्ता आसान किया जा रहा है, दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद उसी मोर्चे पर सख्ती बढ़ती दिखी। अब आम इंसान चाहे किसी भी देश का हो, वो यही पूछेगा कि आखिर सच क्या है। क्या फैसला पहले सोच-समझकर लिया गया था या कोई बयान जल्दबाजी में दे दिया गया क्योंकि होर्मुज कोई मामूली जगह नहीं है। वह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, पूरी दुनिया की सांस की नली जैसा रास्ता है। वहां एक लाइन ऊपर नीचे होने से तेल, कारोबार, जहाज, दबाव, सब कुछ बदल जाता है। यहीं से ईरान के अंदर की तस्वीर पर नजर जाती है। वहां सिर्फ एक दफ्तर से देश नहीं चलता। अलग-अलग ताकतें हैं, अलग-अलग जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं। कोई मैदान देखता है, कोई कूटनीति देखता है, कोई सुरक्षा का बड़ा दायरा देखता है। जब सब एक दिशा में हों तो देश लोहे की तरह खड़ा रहता है लेकिन जब लहजे अलग दिखने लगें तो बाहर वाला दुश्मन तुरंत समझ जाता है कि यहां दरार खोजी जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये नहीं कि किसने क्या कहा। असली बात ये है कि किसकी बात जमीन पर चली। अगर कोई बड़ा बयान आता है और उसके बाद एक्शन बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि या तो अंदर सलाह एक नहीं थी या फिर आखिरी फैसला कहीं और से होना था। यही वह जगह है जहां से बाहर की दुनिया अपने मतलब की कहानियां बनाती है। अमेरिका जैसे देश ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। जहां थोड़ा सा खालीपन दिखा, वहीं अपनी बात ठूंस दी, अपना नैरेटिव खड़ा कर दिया और दुनिया को ये जताने लगे कि सामने वाला बिखर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग तो वैसे भी ऐसे मौकों पर और शोर मचाते हैं।

ईरान इस वक्त बहुत नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है। बाहर से दबाव है। जंग का माहौल है। समंदर के रास्तों पर तनाव है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है। इस्राइल अपना दबाव बनाए हुए है। ऐसे वक्त में किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ मिसाइल या फौज नहीं होती, बल्कि ये होती है कि उसके अंदर फैसले किस तरह लिए जा रहे हैं। अगर ऊपर से एक बात कही जाए और अगले ही दिन उसी बात का रुख बदलता दिखे तो सवाल उठना लाजिमी है। असल मसला यहीं से शुरू होता है। एक तरफ ऐसा संदेश गया कि होर्मुज का रास्ता आसान किया जा रहा है, दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद उसी मोर्चे पर सख्ती बढ़ती दिखी। अब आम इंसान चाहे किसी भी देश का हो, वो यही पूछेगा कि आखिर सच क्या है। क्या फैसला पहले सोच-समझकर लिया गया था या कोई बयान जल्दबाजी में दे दिया गया क्योंकि होर्मुज कोई मामूली जगह नहीं है। वह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, पूरी दुनिया की सांस की नली जैसा रास्ता है। वहां एक लाइन ऊपर नीचे होने से तेल, कारोबार, जहाज, दबाव, सब कुछ बदल जाता है। यहीं से ईरान के अंदर की तस्वीर पर नजर जाती है। वहां सिर्फ एक दफ्तर से देश नहीं चलता। अलग-अलग ताकतें हैं, अलग-अलग जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं। कोई मैदान देखता है, कोई कूटनीति देखता है, कोई सुरक्षा का बड़ा दायरा देखता है। जब सब एक दिशा में हों तो देश लोहे की तरह खड़ा रहता है लेकिन जब लहजे अलग दिखने लगें तो बाहर वाला दुश्मन तुरंत समझ जाता है कि यहां दरार खोजी जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये नहीं कि किसने क्या कहा। असली बात ये है कि किसकी बात जमीन पर चली। अगर कोई बड़ा बयान आता है और उसके बाद एक्शन बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि या तो अंदर सलाह एक नहीं थी या फिर आखिरी फैसला कहीं और से होना था। यही वह जगह है जहां से बाहर की दुनिया अपने मतलब की कहानियां बनाती है। अमेरिका जैसे देश ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। जहां थोड़ा सा खालीपन दिखा, वहीं अपनी बात ठूंस दी, अपना नैरेटिव खड़ा कर दिया और दुनिया को ये जताने लगे कि सामने वाला बिखर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग तो वैसे भी ऐसे मौकों पर और शोर मचाते हैं। उनकी आदत है कि आधा सच पकड़कर पूरा ढोल पीट देते हैं। अगर सामने वाले के यहां एक पल की उलझन दिखी तो उसे हार साबित करने लगते हैं। यही वजह है कि ईरान के भीतर अगर कहीं छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो बाहर उसे बहुत बड़ा करके पेश किया गया लेकिन दूसरी तरफ ईरान के असरदार लोगों की तरफ से जो सख्त रुख सामने आया, उसने ये भी दिखाया कि वहां अभी पूरी कमान किसी एक हाथ से फिसली नहीं है। यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। जंग के दिनों में फैसले सिर्फ किताब देखकर नहीं लिए जाते। उस वक्त हर बात में मैदान, सुरक्षा, सियासत, इज्जत और आने वाले दिनों की चाल सब शामिल होती है इसलिए कभी-कभी ऊपर से जो दिखता है, अंदर की कहानी उससे अलग होती है। हो सकता है कोई बयान दबाव कम करने के लिए आया हो। हो सकता है कोई लाइन बाहर को संदेश देने के लिए छोड़ी गई हो और ये भी हो सकता है कि अंदर सचमुच मतभेद हों, लेकिन जब एक के बाद एक संकेत उलझे हुए आने लगें, तब शक मजबूत होने लगता है कि मामला सिर्फ रणनीति का नहीं, अंदरूनी असहमति का भी है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा ये मानी गई कि वह दबाव में भी जल्दी टूटता नहीं। वहां फैसले भले देर से हों, लेकिन एक बार लाइन तय हो जाए तो फिर उस पर डटे रहने की आदत है। अगर अब वही देश ऐसा दिखने लगे कि अलग-अलग ताकतें अलग सुर में बोल रही हैं तो ये उसके लिए अच्छा इशारा नहीं क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, जंग दिमाग, मनोबल और संदेश में भी जीती जाती है। दुश्मन ये देखता है कि सामने वाला कितना थका, कितना टूटा, कितना बंटा और अगर उसे अंदर की खींचतान की बू आ जाए तो वह और दबाव बढ़ाता है। इसका दूसरा पहलू भी है। कई बार बाहर वालों को जो बिखराव दिखता है, वह असल में किसी बड़े सिस्टम की अंदरूनी बहस भी होती है। फर्क बस इतना है कि ऐसी बहस अगर बाहर लीक हो जाए तो उसका नुकसान बहुत होता है क्योंकि फिर लोग फैसला नहीं, फूट देखने लगते हैं। आज ईरान के साथ यही हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि वहां असली लाइन कौन तय कर रहा है। कौन सख्त है, कौन नरम है, कौन बातचीत चाहता है, कौन मोर्चा कड़ा रखना चाहता है और जब ये सवाल आम हो जाएं तो समझिए कि दुश्मन अपना काम आधा कर चुका है। इस पूरे मामले में सबसे यादा गौर करने वाली बात ये है कि जंग के बीच एक देश को अपने लोगों में यकीन पैदा करना होता है। लोगों को लगना चाहिए कि ऊपर बैठे लोग एक हैं, समझदार हैं और हर कदम सोचकर उठा रहे हैं। अगर आम लोग ही उलझन में पड़ जाएं कि अभी सच क्या है तो यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। बाहर की नाकेबंदी, भीतर का दबाव, चारों तरफ दुष्प्रचार और ऊपर से अलग-अलग आवाजें, ये मिलकर किसी भी देश को मुश्किल में डाल सकती हैं। आखिर में बात सीधी है। ईरान इस समय सिर्फ बाहर की जंग नहीं लड़ रहा, उसे अपने भीतर की तस्वीर भी संभालनी है। अगर अंदर की लाइन साफ रही तो बाहर का दबाव भी झेला जा सकता है लेकिन अगर अंदर ही बात उलझी रही तो दुश्मन को यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंग के दिनों में बंदूक से पहले भरोसा बचाना पड़ता है और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होता है, जब बाहर का हमला कम और अंदर की उलझन यादा दिखने लगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पैसलवेला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

सीएम के विजन का कमाल, कूड़े के पहाड़ को बना दिया पर्यटन स्थल

गोरखपुर।

नजर बदलने से नजारा कैसे बदलता है, इसका जीवंत उदाहरण रापती नदी का एकला बंधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से जो एकला बंधा कूड़े का पहाड़ बन गया था, वह अब शहर के एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कर एकला बंधा पर नगर निगम ने ईको पार्क बना दिया है। इसके सामने की सड़क को भी फोरलेन बना दिया गया है। इस ईको पार्क और इसके सामने से बाघागाड़ा तक जाने वाली फोरलेन सड़क को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल (गुरुवार) को लोकार्पित करेंगे। इस समग्र परियोजना पर 41.50 करोड़ रुपये की लागत आई है। रापती नदी पर राजघाट पुल के समीप एकला बंधा पर कूड़े का विशाल ढेर पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। इस लिगेसी वेस्ट में मीथेन गैस उत्सर्जन के कारण कई बार स्वतः आग भी लग जाती थी। दुर्गंध और वायु

*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ईको पार्क का लोकार्पण

*पुराने कूड़े के ढ़ेर का निस्तारण कर बनाया गया है ईको पार्क, 23 अप्रैल को होगा जनता को समर्पित

*ईको पार्क के सामने फोरलेन सड़क का भी सीएम योगी के हाथों होगा लोकार्पण

प्रदूषण आसपास की आबादी के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ था। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल बताते हैं कि दशकों से इकट्ठा कूड़े के निस्तारण के लिए सीएम योगी के मार्गदर्शन में नगर निगम ने एक कार्ययोजना बनाकर काम शुरू किया और सुखद परिणाम आज सामने है। नगर आयुक्त के अनुसार बायो रेमेडिएशन के माध्यम से नगर निगम ने 2.26 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कराकर 40 एकड़ भूमि को मुक्त

कराया। इतने बड़े क्षेत्रफल में जमीन कूड़ामुक्त हुई तो इसे सिटी फॉरेस्ट और ईको पार्क के रूप में विकसित किया गया। अब लोग यहां प्राकृतिक एवं स्वच्छ वातावरण में पिकनिक मनाने आ सकेंगे। यहां वाकिंग ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं, जहां लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकेंगे। योग और ध्यान के लिए अलग स्थान हैं। बच्चों के लिए भी सुरक्षित किड्स जोन का विकास किया गया है। इसके अलावा नगर निगम ने ईको पार्क के सामने से होकर बाघागाड़ा तक जाने वाले 2.90 किमी लंबे मार्ग पर फोरलेन सड़क बनवा दिया है। इस फोरलेन सड़क के डिवाइडर पर ग्रीन बेल्ट भी विकसित किया गया है।

समग्र परियोजना पर आई 41.50 करोड़ रुपये की लागत

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण, ईको पार्क के विकास और फोरलेन सड़क निर्माण पर नगर निगम ने कुल 41.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। विशाल कूड़े के ढेर को निस्तारित करने में 9 करोड़ रुपये जबकि ईको पार्क बनाने में 4.50 करोड़ रुपये की लागत आई। फोरलेन सड़क बनाने में 28 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

ईको पार्क में स्वछ स्कूल अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री

ईको पार्क एवं फोरलेन सड़क के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वछ स्कूल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। यह अभियान, स्वछ भारत मिशन 2.0 के तहत सिटी लीडरशिप का विशेष कार्यक्रम है। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव का कहना है कि स्वछ स्कूल अभियान केवल स्वछता का कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि यह आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी माध्यम है। स्वछ स्कूल अभियान के जरिये स्थायी व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वछता एवं

सफाई, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, मासिक धर्म स्वछता और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इस अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वार्ड, जोन और नगर स्तर पर वेस्ट टू आर्ट, निबंध, क्विज, रील्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल स्टार रेटिंग प्रणाली के माध्यम से स्कूलों को 1 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार स्वछ स्कूल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष से आकलन कराया जाएगा।

धूप काली माई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन पूजन, भक्ति भाव से गूंजा पडरौना

पडरौना, कुशीनगर।

श्री श्री धूप काली माई मंदिर समिति के तत्वावधान में भगवान शिव एवं पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य एवं श्रद्धापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विधि-विधान से हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था प्रकट की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल भी शामिल हुए और उन्होंने समस्त श्रद्धालुओं के साथ पूजन-अर्चन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोचारण, हवन और भजन-कीर्तन से भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं पंचमुखी हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करते हुए पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। समिति का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह, रमाशंकर शाह, संतोष मिश्रा, अजय शाह, आशुतोष दीक्षित, उग्र साह, दीपक त्रिपाठी, शेषनाथ साह, आदित्य गुप्ता, आलोक गुप्ता, साजन शाह, कृष्णानंद मिश्रा, रेखा देवी, कलावती देवी, मंजू देवी, आराधना त्रिपाठी, रेनू दीक्षित, आशा देवी, कविता सिंह, पिंकी चतुर्वेदी सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कुशीनगर सीबीएसई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का गठन, डॉ. अरुण श्रीवास्तव बने अध्यक्ष

कुशीनगर।

जनपद के सीबीएसई विद्यालयों के समन्वय एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कुशीनगर सीबीएसई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का गठन आपसी सहमति से किया गया। सर्वसम्मति से सेंट जेवियर्स पडरौना के निदेशक डॉ. अरुण श्रीवास्तव को सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ अन्य पदाधिकारियों का भी चयन कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में सुरेन्द्र प्रताप सिंह (संरक्षक), राजीव कुमार (महासचिव), जय प्रकाश सिंह (सचिव), पशुपतिनाथ जायसवाल (उपाध्यक्ष), अमित कुमार श्रीवास्तव (कोषाध्यक्ष) एवं पवन कुमार राय (मीडिया प्रभारी) शामिल हैं। सभी पदाधिकारियों का चयन आपसी सहमति से किया गया, जिसके बाद उपस्थित सदस्यों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जनपद के लगभग 50 सीबीएसई विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों के सर्वांगीण विकास, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर छात्र कल्याण, शिक्षकों के क्षमता विकास और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। अंत में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने तथा कुशीनगर के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

आनंदनगर महराजगंज । फरेंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत बजारडीह के पास तेज रफ्तार से आ रही एक कार सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह उछल कर सड़क के किनारे जा गिरा और गम्भीर रूप से घायल हो गया।अगल बगल के लोगों ने आनन-फानन में उठा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी फरेंदा लाये जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शैलदह उर्फ कवलदह निवासी शम्भू का 25 वर्षीय बेटा नीरज ट्रेक्टर लेकर फरेंदा की ओर से आ रहा था एकाएक ट्रैक्टर खराब हो गया और सड़क के किनारे खड़ा कर रोड पार कर रहा था तब तक गोरखपुर की ओर आ रही तेज रफ्तार की कार ने सड़क पार कर रहे नीरज को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह उछल कर सड़क के किनारे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।अगल बगल के लोगों ने मुकामी पुलिस को सूचना दी घटी घटना स्थल पर पुलिस पहुंच कर लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी फरेंदा लायी जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। उक्त व्यक्ति पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था वहां की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के सहयोग से कार का नंबर मिला तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है समाचार लिखे जाने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

जांच के बाद सख्ती, कालेज की खामियां सुधारने में जुटे जिम्मेदार

निचलौल।

क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कालेज बाली में जिला विद्यालय निरीक्षक के जांच में साफ सफाई से लेकर कई खामियां मिली थी।

इस मामले में सख्ती करने पर कालेज के जिम्मेदार खामियों को सुधारने में जुट गए है। सोमवार को कालेज परिसर में उगी झाड़ियों से लेकर शौचालय तक की साफ सफाई शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं कालेज में नामांकन करने सहित रजिस्टर को दुरुस्त करने में भी जिम्मेदार जुटे रहे। जानकारी के मुताबिक बीते 17 अप्रैल को जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कालेज बाली औचक पहुंच निरीक्षक किए थे। इस दौरान मिला कि कालेज में नवीन शैक्षिक सत्र 2026-27 में पढ़ाई के

कालेज में शौचालय की सफाई करते प्रधानाचार्य

समय सारणी का निर्माण नहीं किया गया है। जबकि कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में शिक्षक सूर्यकान्त विश्वकर्मा पढ़ाते हुए पाये गये। कालेज के कई कक्षाओं में दुर्व्यस्थाएं देखने को मिली। खिड़कियों में दरवाजे तक नहीं थे। कालेज में महज 164 विद्यार्थी उपस्थित पाये गये। बालिका व बालक के शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इसी तरह कुछ शिक्षकों की भी लापरवाही देखने को मिली थी। इस मामले में विभाग की ओर से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सख्ती शुरू हुई, तो कालेज के जिम्मेदारों में हलचल तेज हो गई। ऐसे में जिम्मेदार कालेज की खामियों

जिला विद्यालय निरीक्षक के जांच में आरआईसी कालेज में मिली थी खामियां

को सुधारने में जुट गए है। कालेज के प्रधानाचार्य गिरजाशंकर अग्रवाल ने बताया कि कालेज परिसर में उगी झाड़ियों को काटने, शौचालय की सफाई, बच्चों की नामांकन, शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई के लिए समय सारणी सहित अन्य जरूरी कार्यों को पूर्ण कर ली गई है। इन्होंने आगे कहा कि पिछले सत्र में कालेज में कक्षा छह से लेकर इंटरमीडिएट तक करीब 1600 छात्र पंजीकृत थे। इस सत्र में अब तक 49 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। कालेज में छात्रों को समय सारणी के अनुसार बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षकों को निर्देशित किया गया है।

पारा 45डिग्री के पार- दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी, यूपी से राजस्थान तक लू का अलर्ट

नई दिल्ली। देश में गर्मी का असर इस साल और तेज होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल से जून तक कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मार्च के अंत में जारी किए गए पूर्वानुमान में साफ संकेत दिए गए थे कि इस गर्मी में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस गर्मी का सबसे ज्यादा असर देश के कई बड़े हिस्सों में देखने को मिल सकता है। पूर्वी और दक्षिण भारत में दक्षिण बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और इंडो-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान तेजी से बढ़ सकता है, जिससे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम और मध्य भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि दिन के साथ रात में भी हवाओं में तपिश महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से फिलहाल एक हफ्ते तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों के 11 जिलों में हीटवेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी किया है। वहीं पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे छह जिलों में उष्ण रात्रि यानी बेहद गर्म रात होने की भी बात कही है।भीषण गर्मी और तपिश किसानों, मेहनतकश और आमजन पर कहर बनकर टूट रही है। उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में गर्मी अब तेजी से विकराल रूप लेती जा रही है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में ही तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है।

रविवार को प्रदेश के कई शहरों में पारा 42 डिग्री के पार चला गया, जिससे लोगों को दिनभर तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा। छतरपुर जिले के नौगांव में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो इस सीजन का अब तक का सबसे उच्च स्तर है। राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के महीने में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालात को देखते हुए मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी तीन से चार दिनों के लिए हीटवेव का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में तेज उछाल के कारण राज्य के कई जिलों में लू जैसे हालात बन गए हैं।

जम्मू सड़क हादसा में 21 की मौत

यात्री बोले- तेज रफ्तार बस का टायर फटा, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका; 100 मीटर नीचे गिरी

उधमपुर।

जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस कगोत के पास सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग रामनगर से उधमपुर में अपने रोजाना के काम पर जा रहे थे। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों के मुताबिक बस ओवरलोड थी, रफ्तार भी तेज थी। कगोत नाले के पास अचानक बस का टायर फट गया। इससे ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका। और बस सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बताया कि हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। घायलों का इलाज नजदीक उधमपुर में किया जा रहा है। इधर, पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले लोगों के लिए संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है।

यात्री बोले- बस तेज रफ्तार में थी, टायर फटने से कंट्रोल छूटा

हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे की वजह बस का ओवरलोड और तेज रफ्तार होना था। घायल यात्रियों से पूछा गया तो वे बोले कि ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा था। बस का टायर फटने से वह स्पीड कंट्रोल नहीं कर सका। जिसके कारण वह करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिर गई।

बस की चपेट में ऑटो भी आया

बस नीचे सड़क पर उलटी गिरने से पहले एक ऑटो-रिक्शा को कुचलती हुई गई। अधिकारियों ने बताया कि ऑटो-रिक्शा में सवार लोगों को चोटें आईं, लेकिन वे बच गए। हादसे के बाद उसी रास्ते से गुजर रहे सेना के एक काफिले ने बचाव अभियान की कमान संभाली। बाद में एक हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया।

जापान के समंदर में आया 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, बंदरगाह से टकराई सुनामी की पहली लहर

टोक्यो। जापान में सोमवार को 7.5 रिक्टर तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक, इवाते प्रांत और होक्काइडो और आओमोरी के कुछ हिस्सों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। भूकंप इवाते के सानरिकु तट से करीब 100 किमी दूर और 10 किमी की गहराई पर आया। भारत के समयानुसार यह भूकंप दोपहर 1:23 बजे आया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में, 0 से 7 के जापानी पैमाने पर इसकी तीव्रता 5 से ऊपर थी। अधिकारियों ने लोगों से तुरंत ऊंचे इलाकों में जाने और तट तथा नदियों से दूर रहने की अपील की है। राहत और आपात सेवाएं हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संभावित नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भूकंप के झटके

रिकॉर्ड होने के बाद तोहोकू शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा को टोक्यो स्टेशन और शिन-आओमोरी स्टेशन के बीच अस्थायी रूप से रोका गया। ऑपरेटर ने बताया कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया। यामागाता और अकिता शिंकानसेन सेवाएं भी बंद की गईं। इवाते प्रिफेक्चर में सभी लोकल ट्रेन सेवाएं रोकी गईं। होक्काइडो में कुछ लोकल लाइनें भी बंद हैं। शिन-चितोसे और सेंडाई एयरपोर्ट के ऑपरेटरों ने कहा कि भूकंप के बावजूद उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक, इवाते के कुजी पोर्ट पर 80 सेंटीमीटर की सुनामी लहर टकराई और पानी बढ़ रहा है। मियाको पोर्ट पर 40 सेंटीमीटर की लहर आई। आओमोरी के हाचिनोहे पोर्ट पर 30 सेंटीमीटर लहर दर्ज हुई। होक्काइडो के उराकावा टाउन और मियागी के इशिनोमाकी आयुकावा में 20 सेंटीमीटर तक की लहरें दर्ज की गईं।

प्रभावित इलाकों में लोगों को दी गई सलाह

प्रभावित इलाकों में लोगों को समुद्र किनारे और नदियों के मुहानों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां पानी तेजी से भर सकता है। बचाव और आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बता दें कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह प्रशांत अग्नि वलय क्षेत्र में स्थित है, जहां चार बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। यहां हर साल करीब

राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग- कर्मचारियों को बाहर निकाला

बालोतरा/बाड़मेर।

बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले आग लग गई। सोमवार दोपहर 2 बजे रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगी। धुएं का गुबार उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया है। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें मंगलवार को

कई घंटे बाद काबू पाया गया; आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे, कार्यक्रम स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी के जिस हिस्से में आग लगी है, वह जगह सभा स्थल से 800 मीटर दूर है। इस सभा स्थल में कल पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में पाइप लाइन से आने वाला कच्चा तेल इसी यूनिट में आता है। इस यूनिट में क्रूड ऑयल रिफाइन होकर अलग-अलग यूनिट में भेजा जाता है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद ही नुकसान और इसके कारणों का आकलन किया जा सकेगा। घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

योगी ने बंगाल में भरी हुंकार, महिला आरक्षण पर कांग्रेस और टीएमसी को जमकर कोसा

मेदिनीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने मेदिनीपुर में चुनावी जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को जमकर कोसा। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों के रुख को लेकर कहा कि महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस, टीएमसी और इंडिया गठबंधन ने 60 साल से ज्यादा भारत पर राज किया। लेकिन उनके पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ये लोग बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल तोड़ा और उनका अपमान किया। भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और एसपी सभी ने हाल के संसद सत्र के दौरान महिला आरक्षण को लेकर जो व्यवहार दिखाया है इसकी भाजपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। आपने देखा होगा कि कैसे इन पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन एक्ट में संशोधन को पास होने से रोका, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 2029 में लागू करना चाहते थे। यह दिखाता है कि आदिवासी आबादी का अपमान करना, युवाओं का अपमान करना, किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना उनकी फितरत बन गई है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। वे अब इस तरह के भ्रष्टाचार और गलत कामों में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच बना हुआ है, जहां दोनों पक्ष महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे से अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं फिलहाल अब देखना होगा इस चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है।

बंगाल दौरे को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का मोदी पर वार, बोले- क्या सीएम बनना चाहते हैं?

कोलकाता। पश्चिम बिहार के कूच बिहार में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और अपने आधिकारिक काम की अनदेखी कर रहे हैं। रैली में खरगे ने सवाल उठाते हुए कहा क्या मोदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पीएम के लगातार चुनावी दौरे से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर भी हमला

उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल को लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर किया गया। कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2029 से लागू होना था, लेकिन इसे कमजोर करने का काम किया गया। उन्होंने कहा आपने ही महिला आरक्षण बिल को खत्म किया है, हमने इसके खिलाफ नहीं बल्कि परिसीमन बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम करती रही है। उन्होंने सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जैसी महिला नेताओं का भी जिक्र किया।

होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई पर भड़का ईरान

ट्रंप को दी चेतावनी, कहा- कोई सबक नहीं सीखा, अब नहीं होगी बातचीत

तेहरान। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका-ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वह फिलहाल शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ने अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखा है और अब इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने अमेरिका पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ वह कूटनीति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई करता है। बघाई ने कहा कि ऐसे विरोधाभासी कदमों से भरोसा टूटता है और इससे हालात और खराब होंगे। दरअसल, अमेरिका ने होर्मुज के पास ओमान की खाड़ी में एक ईरानी कार्गो जहाज टौस्का को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक, जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आदेश नहीं माना। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे रोक दिया और मरीन कमांडो ने जहाज को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई को ईरान ने सीधा हमला बताया है।

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच हुए कई समझौते, पीएम मोदी ने की संबंधों की सराहना

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देते हुए कहा कि दोनों देश अब चिप्स से शिप्स तक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी दक्षिण कोरिया के साथ हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों के बाद आई, जो तकनीक, रक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते अब केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर (चिप), इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ग्रीन टेक्नोलॉजी और शिपबिल्डिंग (जहाज निर्माण) जैसे हाई-टेक

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध चिप से शिप तक मजबूत।
तकनीक, रक्षा, व्यापार में कई अहम समझौते हुए।
इंडो-पैसिफिक स्थिरता हेतु साझेदारी महत्वपूर्ण।

और रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए भी बेहद अहम है।

कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इस दौरे के दौरान कई समझौते हुए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाना।

डिफेंस और सिक्योरिटी साझेदारी को मजबूत करना।

ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त पहल।

शिपबिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग।

स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।

व्यापार और निवेश पर फोकस

दोनों देशों ने आपसी व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत, दक्षिण कोरिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, वहीं दक्षिण कोरिया की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने में रुचि दिखा रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

रक्षा और रणनीतिक सहयोग

भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीक साझा करना और रक्षा उपकरणों के निर्माण में साझेदारी शामिल है। यह सहयोग खासतौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। छात्रों के आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया एक मुक्त, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

जज को केस से हटाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अपना जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा, मैडम अगर मेरा जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो यह न्याय के प्रति लापरवाही होगी।

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यदि किसी न्यायाधीश का फैसला ऊपरी अदालत द्वारा बदला जाता है तो किसी भी प्रतिवादी को यह कहने का हक नहीं है कि आमुक जज फैसला करने योग्य नहीं है। जज की क्षमताओं पर फैसला इसकी उच्च अदालत करती है ना की प्रतिवादी। अदालत में अखिल भारतीय देवता परिषद के कार्यक्रमों में न्यायमूर्ति के शामिल होने पर कहा कि वह महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने जूनियर वकीलों और अन्य बार के सदस्यों को संबोधित किया था। केवल अरविंद केजरीवाल की आईडियोलॉजी से सहमति न रखने के चलते यह आरोप गलत है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा मेरा न्यायिक करियर 34 वर्षों का रहा है। क्या अब यह हो सकता है कि जजों को वादकारी द्वारा तय अतिरिक्त परीक्षा पास करनी पड़े कि वे मामले की सुनवाई के योग्य हैं? क्या उन्हें वादकारी द्वारा बनाए गए मानकों के आधार पर पहले खुद को साबित करना होगा? ऐसे में जजों को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी संगठन के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया या उनके परिवार के सदस्य विधि पेशे में नहीं हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि आवेदक ने अपने लिए विन-विन या कैच-22 की स्थिति बना ली है। यदि अदालत खुद को अलग करती है तो उनके दावे सही ठहरेंगे, और यदि नहीं करती है तो वह फिर भी फैसले पर

आबकारी नीति मामले में अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, मैं इन आवेदनों को खारिज कर रही हूं क्योंकि मेरी शपथ संविधान के प्रति है और संविधान हमें बताता है कि निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते। मैं इस मामले की सुनवाई से नहीं हटूंगी।

सवाल उठा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी रणनीतियों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया और संस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा है।न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस मामले में मुझे ऐसी स्थिति में रखा गया है कि यदि मैं खुद को अलग

करती हूं तो क्या होगा और यदि नहीं करती हूं तो क्या होगा। अगर उसे राहत नहीं मिलती है, तो वह कहेगा कि उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। अगर उसे राहत मिलती है, तो वह कह सकता है कि अदालत ने दबाव में आकर फैसला किया। वादकारी स्थिति को अपने पक्ष के अनुसार पेश कर सकता है।

जज को कटघरे में खड़ा करने की इजाजत नहीं

अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता हेगड़े के अग्निपरीक्षा वाले तर्क का संज्ञान लिया, लेकिन सवाल उठाया कि केवल प्रतिकूल परिणाम के डर से किसी आरोपी के कहने पर जज को ऐसी परीक्षा से क्यों गुजरना चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह जज को पक्षपाती साबित करने की कोशिश करे। अदालत ने कहा कि जब किसी मौजूदा जज पर आरोप लगाए जाते हैं, तब भी वही निष्पक्षता लागू होनी चाहिए। कोई भी राजनेता, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, बिना किसी ठोस साक्ष्य के जज के खिलाफ आरोप लगाकर संस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अदालत कक्ष को धारणाओं का मंच नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा दुर्भाग्य से आज मुझे दो पक्षकारों के बीच विवाद नहीं, बल्कि एक पक्षकार और स्वयं मेरे बीच के विवाद पर निर्णय करना पड़ रहा है। वर्तमान आवेदनों को स्वीकार करना जज पर लगाए गए आरोपों को मान्यता देने जैसा होगा। जब ऐसी स्थिति आती है, तो यह अदालत अपने और संस्था के पक्ष में खड़ी रहेगी। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि साक्ष्य मांगने वाली फाइल साक्ष्यों के साथ नहीं, बल्कि इशारों और आरोपों के साथ आई। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, मैं इन आवेदनों को खारिज कर रही हूं क्योंकि मेरी शपथ संविधान के प्रति है और संविधान हमें बताता है कि निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते। मैं इस मामले की सुनवाई से नहीं हटूंगी। अदालत में मुख्य मामले से जुड़े प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। प्रतिवादियों को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत में 29 और 30 अप्रैल को मामले में बहस के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा, पूरे देश में जब भी फैसला सुरक्षित हो जाता है तो ऐसे में कोई भी एडिशनल एफिडेविट रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता लेकिन अदालत ने फिर भी केजरीवाल के एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लिया है। वहीं, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, सॉलिसिटर जनरल सही कह रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है वह सभी लोगों पर बराबर है किसी व्यक्ति विशेष के लिए बदली नहीं जा सकती।

हालांकि, अदालत ने चूंकि केजरीवाल स्वयं अपना पक्ष रख रहे थे ऐसे में उन्हें थोड़ी राहत देते हुए एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर ले लिया। अदालत में केजरीवाल के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है। अदालत ने केजरीवाल को बताया कि इस मामले में 4:30 बजे आज फैसला आना है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 13 अप्रैल को केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चार घंटे से अधिक समय तक हुई लंबी सुनवाई में दोनों पक्षों ने तीखी बहस की, जिसमें केजरीवाल ने खुद कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखीं थीं। इससे पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दाखिल नये हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया था।